Inter College area in general and village Kwali in particular, was damaged by people of another village, Bangaon; and

(d) if so, by when the drinking water supply to the people of village Kwali Patti Gagwarnsin is likely to be restored ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) and (b) The State Government of Uttar Pradesh has informed that as on 1-4-93, there were 107 problem villages which have to face drinking water shortage in district Pauri Garhwal. Five villages have already been provided safe drinking water facilities and 69 more are likely to be covered by 31-3-94. The remaining villages will be covered in 1994-95.

(c) No such report has been received from the State Government of Uttar Pradesh or otherwise.

(d) Does not arise.

AMOUNT SPENT ON THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME IN MADHYA PRADESH

3253. **SHRI AJIT P. K. JOGI :**
CHOWDHRY HARI SINGH :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the amount spent on the rural development programmes in Madhya Pradesh during 1991-92 and 1992-93 and the amount proposed to be spent during 1993-94;

(b) the amount spent on education and health during 1991-92 and the amount proposed to be spent during 1993-94;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh has spent all the amount earmarked during the last year; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) The amount released and spent on major development programmes in Madhya Pradesh during 1991-92 and 1992-93 and proposed allocation during 1993-94 are as under :—

(Rs. in lakhs)

Programme	1991-92		1992-93		1993-94
	Amount released	Amount spent	Amount released	Amount spent	Proposed Allocation
Integrated Rural Development Programme (IRDP)	6535.90	9353.08	6822.18	7336.37	10664.00
Jawahar Rozgar Yojana (JRY)	23885.31	31681.83	33484.98*	29328.16	46440.99
Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP)	3583.00	3287.00	2902.00	2554.00	3191.00

*Includes Rs. 5541.37 lakhs released on 31-3-1993.

(b) Under 'Operation Black Board' scheme, the Government of India has provided assistance of Rs. 846.91 lakhs during 1991-92 and Rs. 1819.00 lakhs during 1992-93 (anticipated) to the State of Madhya Pradesh. Further, Central Government has provided funds to the State of Madhya Pradesh under following Centrally-sponsored schemes during 1991-92 and 1992-93 as Central assistance :

(Rs. in lakhs)

Programme	1991-92	1992-93
(i) National Malaria Eradication Programme	928.36	1203.15
(ii) National Leprosy Eradication Programme	208.62	199.00
(iii) National T.B. Control Programme	33.79	96.91
(iv) Natioal Programme for Control of Blindness.	198.95	146.76

(c) and (d) As may be seen from figures of expenditure in part (a) of the Question, the Government of Madhya Pradesh has spent almost all the amount earmarked during 1992-93.

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि का विकास

3254. **श्री राम करेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में "बंजर भूमि का विकास" करने हेतु जिलावार कौन-कौन से क्षेत्र चुने गए हैं ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंजर भूमि का विकास करने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकारों को धनराशि का दिया जाना

@3255. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्येक विकास खंड में 5 लाख रुपए की दर पर 1752 विकास खंडों में वितरण करने हेतु धनराशि जारी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि यह धनराशि खर्च करके कितने कर्मकारों को रोजगार मिलने की संभावना है और उनमें से प्रत्येक को एक वर्ष में कितने दिन काम मिलने का अनुमान है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान देश में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले 1752 खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने केन्द्रीय अंश के रूप में राज्य सरकारों को 5 लाख रुपए प्रति खंड के हिसाब से रिलीज किए हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए खण्डों की संख्या और अब तक रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए) ।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2430, 20-12-1993 से स्थानांतरित ।